भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2460

शुक्रवार, 13 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर

2460. श्री नीरज डांगी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर के आंकड़े उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर में कमी/गिरावट का देश में रोजगार सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर में देखे गए उतार-चढ़ाव के प्रमुख कारण क्या रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार औद्योगिक उत्पादन वृद्धि को तेज करने हेतु कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, औद्योगिक उत्पादों के समूह के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापने के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर मासिक रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) संकलित करता है और जारी करता है। आईआईपी की वार्षिक वृद्धि दर एमओएसपीआई की वेबसाइट http://mospi.gov.in/latest-releases पर उपलब्ध है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, प्रति वर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार और बेरोजगारी के प्रमुख संकेतकों के सृजन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित कर रहा है। वर्ष 2017-18 से 2024-25 की अवधि के लिए सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के बीच श्रमिक जनसंख्या

अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर का अखिल भारतीय स्तर पर अनुमान नीचे दिया गया है:

वर्ष	श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) [% में]	बेरोजगारी दर (यूआर) [% में]
2017-18	46.8	6.0
2018-19	47.3	5.8
2019-20	50.9	4.8
2020-21	52.6	4.2
2021-22	52.9	4.1
2022-23	56.0	3.2
2023-24	58.2	3.2
2024-25*	57.7	3.2

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

पीएलएफएस की सर्वेक्षण अवधि जुलाई से जून है।

** वर्ष 2024-25 के लिए ऑकड़े जनवरी-24 से दिसंबर-24 की अवधि के हैं।*

अखिल भारतीय स्तर पर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में वर्ष 2017-18 के बाद से वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, जिसकी पुष्टि घटती बेरोजगारी दर (2017-18 में 6.0% से घटकर 2024-25 में 3.2% हो गई) से होती है।

(घ): सरकार ने देश में निवेश को बढ़ावा देने और अधिक औद्योगिक कार्यकलापों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से उपयुक्त नीतिगत जरिए के माध्यम से देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए एक सक्षम ईकोसिस्टम प्रदान करती है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) स्कीम आदि। आर्थिक वृद्धि को सुदृढ़ करने, रोजगार सृजित करने और वैश्विक स्थिति को मजबूत करने

के लिए, सरकार ने अपनी वैश्विक व्यापार साझेदारी का निरंतर विस्तार किया है, उदाहरण के लिए, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते में 15 वर्षों के दौरान 20 बिलियन अमरीकी डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता शामिल है, जबकि भारत- ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते में 15 वर्षों के दौरान 100 बिलियन अमरीकी डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता का प्रावधान किया गया है, जो आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन में सहायता कर रहा है।

*****